RAJYA SABHA

Tuesday, the 22nd December, 1992
1st Pausa, 1914 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock. Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Disruption of Telecom Services in Kashmir

*401. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that telecommunication links in the Kashmir valley were cut off with the rest of the world recenty;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what remedial 'action has been taken by Government to maintain the normal telecommunication services in the valley?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Jammu-Srinagar Microwave link failed on 10th October following an attack on the Benkote Microwave Repeater Station by armed militants who completely damaged the telecom installations by burning them, thus disrupting the telecom facilities to and from Kashmir Valley to the rest of the country which was the only major link. Immediate restoration was not possible since the place was not ac-cesible to the Telecom personnel due to security risks

On 11th October, 92 the maintenance personnel reached the site. As the damage to the equipment was beyond repair, the communication was partially restored with an emergency satellite communication terminal.

More circuits were provided by reviving the old harrow band microwave system and Statellite Earth Station to augment the circuits between Kashmir Valley and the rest of the country.

STD service to Srinagar is likely to be restored after the current winter is over.

श्री एस० एस० अल्लुवालिया : सभापति महोदय, जम्मू और श्रीनगर का सूक्ष्म तरंग संचार सम्पर्क पिछले 10 अक्तूबर से टूट गया है। आतंकवादियों के हमले में वह पूरा संचार संयंत्र जो था वह तोड़कर नष्ट कर दिया गया है। पर आज तक उस पर कोई भी कार्यवाही सरकार की तरफ से नहीं हो सकी है जिसके कारण अभी भी जम्मू काश्मीर में इतने आतंकावाद और इतने अलगाववाद की भावना होने के बावजूद भी, बहुत सारा सामान जो देश और विदेश में निर्यात किया जाता है उसमें बड़ी असुविधा हो रही है वहां एस०टी०डी० फैसिलिटी नहीं होने के कारण। मंत्री जी इसके लिए क्या कार्यवाही करेंगे ? मैं जहां तक समझता हूं माननीय मंत्री जी श्री राजेश पायलट जी ने इस सदन में पहले भी बताया था कि गांवों में, दूरदराज इलाकों में जहां पर टलीफोन एक्सचेंज नहीं लगाये जा सकते हैं वहां पर वायरलेस टलीफोन के माध्यम से एस०टी०डी० की फैसिलिटीज देते हुए वायरलेस टलीफोन बैठाये जायेंगे। इसलिए क्या ऐसे संयंत्र लगाकर, इलाके में पब्लिक बूथ खोलकर, जब तक यह पूरा सूक्ष्म तरंग संयंत्र नहीं लगाया जा सकता है, तब तक के लिए आल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने का क्या कोई बंदोबस्त इन्होंने किया है ?

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: Sir. the communications were restored on the 11th of October itself and within a week some more channels were provided by reviving the old narrow band microwave system. A satellite earth station has also been established to augment

the. ..circuits. Rights now 100 channels are available for the public besides 35 channels on the hotline. At the moment, STD is not functioning and we hope this will also start fuctioning as soon as we complete the work which has been taken up. Because of the winter season, we are - not able to make progress with the work. Very soon, STD will also be restored. For the present, we have made arranegements to see that trunk calls materialise as fast as possible.

श्री एस० एम० अस्लुबालिया : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जैसे बताया कि 100 चैनल्स काम कर रहे हैं। पर मेरी जहां तक इन्फारमेशन है ये 100 चैनल्स सिर्फ सरकारी कार्यालयों और पुलिस के वास्ते ही चलाये जा रहे हैं। वहां जनता को कोई भी चैनल नहीं दिया गया है। प्रेस वालों को भी कोई चैनल नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि एस०टी०डी० का भी कोई काम नहीं शुरू हुआ है। पर मुझे पता है कि वहां एस०टी०डी० के तीन चैनल काम कर रहे हैं और तीनों चैनल सिर्फ डी०जी०पी० के आफिस में और गवर्नर के आफिस में वर्क करते हैं और कहीं नहीं करते। मेरा कहना है कि अगर ये एस०टी०डी० चैनल काम नहीं कर सकते हैं तो इनको क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? दूसरा, सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि मुझे पता लगा है कि आजाद काश्मीर के इलाके में कुछ हाई पावर सेटलाइट के रिसीवर्स लगाये हुए हैं पाकिस्तान ने जोकि यहां के लोग, हमारे इस पार के लोग अपने छोटे-छोटे रिसीवर्स के थ्रू और वायरलेस टेलीफोनस के एस०टी०डी० पर बात उसके माध्यम से कर सकते हैं। इस पर क्या मंत्रालय को कोई जानकारी है और अगर जानकारी है, तो क्या कार्यवाही कर रहे हैं

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलेट) : सभापति जी, यह बात सही है कि 10 अक्तूबर को यह जो हमारा कम्युनिकेशन सेटअप था वह आतंकवादियों ने जला दिया था और इक्विपमेंट ही नहीं, उन्होंने बिल्डिंग को भी नष्ट कर दिया था। हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने जल्दी ही उसको काबू में पाया और एक ही दिन के अंदर ट्रंक चैनल्स हमने चालू कर दिये थे। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि कश्मीर में खास तौर पर जो फ्रूट मर्चेन्ट्स हैं, जो फल इधर-उधर एक्सपोर्ट करते हैं, उनको इससे बड़ी कठिनाई पड़ी। पहले शुरू में उसमें 350 चैनल्स उस कम्युनिकेशन सिस्टम में एवेलेबल थे। आजकल सौ चैनल्स हमारे पास हैं। सो हमने वह एस०टी०डी० को जान-बूझ कर बंद कर रखा है, जिससे ट्रंक चैनल्स से खास लोगों को काल मिलती रहें।

अगर हम एस०टी०डी० को खोल देंगे, तो उसमें यह नहीं पता चलेगा कि सबको यह सुविधा उपलब्ध है या नहीं। अब अर्जेंट काल ज्यादा से ज्यादा एक-सवा घंटे में मिल रही है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि जो कुछ जरूरत सुरक्षा की वजह से एस०टी०डी० चैनल्स है, वह सरकारी अधिकारियों को, गवर्नर को, डी०जी० पुलिस को यह दिये हुए हैं। लेकिन आज जब बात चल रही थी, तो अधिकारी वहां से आये हुए थे। मैंने उनसे कहा है कि एस०टी०डी० पी०सी०ओज० श्रीनगर में—अगर एस०टी०डी० सब को नहीं दे पायें, तो एस०टी०डी० पी०सी०ओज० श्रीनगर में ऐसा कम्युनिकेशन सेंटर खोल कर हम दो-चार चालू कर दें, जिससे यह सुविधा नागरिकों को मिल सके। मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव को लागू करवाऊंगा।

जहां तक आम संचार की बात है, उसमें थोड़ा वक्त और लग सकता है। लेकिन बहुत जल्द सामान्य संचार की स्थिति वहां पर ला दी जाएगी।

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, what happened in Kashmir on 10th October is a serious matter. I do not understand why the Government particularly the Communications Ministry, remained com-

placent about it. So many subversive activities are going on in Kashmir, including killings. In spite of that, the Government remained complacent and there was no protective measure to maintain and protect the telecommunication networks and links beween Kahsmi'.- and the rest of the world. Because I am very much concerned about the complacent attitude of the Government, I would like to know from the hon. Minister what measures they have adopted for proetect-ing and maintaining the telecommunication networks and links in Kashmir so that they are not snapped by terrorists as they are an easy target and once the link is snapped they can commit any mis-chief. What protective measures are they taking for protecting and maintaining the link? Incidents of this type may happen in future also because subversion continues. So, what are the alternative arrnagements the Government is thinking of in case such incidents recur in future? What will be the alternaive arrangements made by the Government so that the link can be maintained between Kashmir and the rest of the WORLD?

SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU: Mr. Chairman, it is a fact that there was no protective arrangement earlier for microwave stations. But, after the incident, we requested the State Government and one platoon of the CRPF is posted there. Now. they are guarding the installations. Regarding the future, we are planning to have two earth stations in Srinagar in very secured place so that they may not be vulnerable to any attacks by the terrorists. The work has started and very soon it will be completed.

SHRI SUKOMAL SEN: Sir. it is very strange that the Government is so complacent that they did not take any protective measures.

MR. CHAIRMAN: He has said that now measures are being taken.

SHRI RAJESH PILOT: Mr Chairman, Sir. let me explain it very clearly to the House. The sitution in Kashmir is known to the whole country. It is also a fact that we have problems in Kashmir. We are not hiding it away from the House. There are problems. And whatever best could be done, we have been trying to do. You will appreciate the conditions under which our exchanges are functioning. Our people are sleeping in a very secure corridor somewhere; we bring them by a bus in the morning; we keep guard for them in the exchange; and then again, drop them back. The House must also appreciate under what conditions the workers are discharging their duties. In rural areas, it is even worse. Under those circumstances, still, the exchanges were reconnected within one day which is a very good efforts on their part. I request hon. Members to consider these factors and the prevailing situation in the Valley also.

श्री सच्चिदानन्द : सभापति जी, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि यह सारा काम करने के लिए अनुभवी और उत्साही कर्मचारियों और अधिकारियों का वहां भेजा जाना आवश्यक है। आपके मंत्रालय से स्वाभाविक इन कामों के लिए अधि-कारियों को आप भेज रहे होंगे और भेजते होंगे। इन में से कितने अधिकारियों ने वहां पर मौजूद स्थानों पर अपने पदों को संभाला है और बाकी कितने स्थान रिक्त हैं ? रिक्त स्थानों को भरने के लिए आपकी क्या योजना है ? कोई विशेष सुविधा उन अधिकारियों को देने की आपकी सरकार की कुछ योजना में है या नहीं ? यह मंत्री जी बताने की कृपा करें।

श्री राजेश पायलट : चेयरमैन सर, हालांकि इस सवाल के लिए मुझे अलग से नोटिस दी जाए ताकि मैं सारी इन्फार्मेशन हाउस को दे सकूं। लेकिन ए,क बात सही है कि ज्यादतर अधिकारी काश्मीर की पोस्टिंग के लिए उतने उत्सुक नहीं हैं जितने कि होने चाहिए यह तो सही बात है कि जब पोस्टिंग होती है तो उसमें कई बार कैंसलेशन होती है। हमारे ही साथी कह देते हैं कि इसको मत भेजो। अभी थोड़ा रोक दो। माननीय सदस्य

इस बात को मानेंगे । बहुत सी बातें मुझ पर आप माननीय सदस्यों की तरफ से आती हैं कि कोई बात नहीं किसी और को भेज दो। इसको रोक दो। इसके घर में कोई तकलीफ है, इसके घर में परेशानी है। तो यह बात सही है कि उस एरिया में अभी अधिकारी उतने नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कारण नहीं हैं कि हमारा काम रुक रहा हो। काम चल रहा है और जितना ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज वहां पर दे पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पर और कम्युनिकेशन चैनल्स सारे हम चालू रखे हैं ।

श्री सच्चिदानन्द : मुझे यह पूछना था कि उनको क्या कोई विशेष सुविधायें या ऐसे आप देने की घोषणा करेंगे जिससे वहां जा सकें? अर्थात् स्पेशल सेंटिव्ज।

श्री राजेश पायलट : अभी ऐसी कोई खास नीति सरकार की नहीं है जो कि कोई खास इंसेंटिव उन इलाकों को दिया जाए ।

SHRI G. SWAMINATHAN: Sir, ex cept echoing the sentiments of Shri Ahluwalia I have not to say much. I was also a member of the Parliamentary delegation to Kashmir in the end of October or in early November. We were also not able to phone up anywhere. The whole thing was disrupted. Some of the local people said that the situation had been grave for a long time. Even the normal channels had not been working properly and consequent to that the trade channels were also not working. That was the feeling expressed by them.

I think when you are making it all right, it should be not for the Government only, it should be for the people also. Then only normalisation can continue. Therefore, will you take up the task on priority basis, and when wild the situation be normalised?

SHRI RAJESH PILOT: Sir, it is a fact that communication in the Valley has been one of the good communications in the country and we had all these channels available to the public also- As hon. Ahluwaliaji mentioned, it is a good suggestion that all we really develop a perfect communication, we must give some STD facility out of these 100 channels to the public so that they can do it from a public booth. At least, I am planning to have a telecom. Centre where 4-5 booths are available. But I have got a lot of problems. In Kashmir things are slightly different. Firstly, no public man may come up *to* take a PCO because there they take it in a different sense, but I can assure you that very, very soon re-establishment of the communictaion will take place. I may not be able to give the exact date because the situation there is bad. There is snowing, the communication channels are at a place called Benkote which is at a height. We are lifting it by helicopters to the place, from there again taking it with the help of labour to the hill-tops. So, it will take some time, but give me time. I may not be able to give the exact date as on today, but at the earliest I will restore it.

SHRI JAGMOHAN: Would the hon. Minister be pleased to indicate whether it is not a fact that very serious instructions already existed that all the vital installation should be protected? In view of the lapse of not protecting them adequately, has any enquiry been held to see whether the arrangements for protection of vital installation were adequate or not? If not, why has the enquiry not been held, because on the very first day I had issued these instructions?

SHRI RAJESH PILOT: I am sure, you must have briefed the person who took orders from you to follow them very seriously. Security is one of the foremost duties of the State Administartion and I am happy that they are doing their best as far as our installations are concerned. As my colleague said, the security was not up to that degree as has been beefed Up now. Earlier also it is not that it was totally unguarded, or there was no guard. But the strength was not that adequate, and no one

expected it because we don't expect that they would go and burn the installations there. Normally it is in some areas declared by them where we had some apprehensions, but this is far away from these; it is near Banihal. You really have to climb 6,000 feet. So we were thinking of much less apprehended areas than others. So, now the State Government has taken more effective measures, and I will personnally monitor it. As far as the inquiry is concerned, I will find out from the State Government and come back to you

MR CHAIRMAN: Shri Ramji Lal.

SHRI -JAGMOHAN: Instructions were there at this very height, Banihal.

MR. CHAIRMAN: Please wait. Shri Ramji Lal.

श्री रामजी लाल : धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिस तरह काश्मीर में यह सचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है, इसी तरह देश और दुनिया में दूसरी जगह हो सकती है और इसे जोड़ने के लिए सरकार इमीडिएट स्टेप्स उठाती है। तो सरकार इस तरफ विशेष ध्यान देने के लिए क्या कोई सेल संचार भवन में खोलने का विचार रखती है ?

श्री राजेश पायलट : सभापति जी, काश्मीर के हालात आज खास हालातों से गुजर रहे हैं और हर जगह ऐसी कोई बात नहीं है कि हर जगह हमारे इंस्टालेशंस को उतना ही खतरा हो, लेकिन जहां तक गवर्नमेंट प्रापर्टी है, वह सरकार सब जगह गार्ड करती है। सरकार ख्याल रखती है कि सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान न हो और सरकारी संपत्ति सुरक्षित रहे। वह सरकार का एक फर्ज है और सरकार उसे पूरी तरह ख्याल कर के निभा रही है ।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Our Telecommunications Ministry functions under an Act which is more than 110 years old. Mr. Chairman, about an year ago 1 had asked a similar question and at that time the same hon Minister had assured this House that very soon he would come to the House with an amendment. More than a year has passed but there seems to be no movement towards modernization of our laws because, in 1883 when the earlier Act was passed there were no computers, no telecommunication links. So. the outdated thing has got to be replaced as early as possible. My specific question is this: There were some press reports recently that the Central Government has been considering delegation of some of the powers that it ' holds to the State Governments, and I wish particularly to refer to a letter which, I believe, the Secretary, Department of Electronics, has written to the Chief Secretaries of the State Governments that they could put in applications so that they can be authorized to have their own telephone exchanges for industrial areas, for socio-economic development and for government. What is the response of the Ministry of Telecommunication to this proposal of the Department of Electronics?

MR. CHAIRMAN: It is a very general question—not related to thisv Does tha Minister want to answer? It doesnt elate to this question... *(Interruptions).* No? Dr. Sanjaya Sinh.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Sir, it is a specific question.

MR. CHAIRMAN: It doesn't relate to this.

DR JINENDRA KUMAR JAIN: Sir, I said, the Department of Electronics has written a letter to the Chief Secretaries.

MR. CHAIRMAN: The quesion is about telecommunications in Kashmir... *(Interruptions)* I rule it out.

DR JINENDRA KUMAR JAIN: Sir, allow me to.. . *(Interruptions)*

MR. CHAIMRAN: Will you please sit down?.. . *(Interruptions)*.. You will have to sit down. This is not relevant.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Is the authority delegated to Jammu and Kashmir Statet

डा० संजय सिंह : सभापति महोदय, प्रमुख सवाल से संबंधित कई सवाल माननीय मंत्रीजी से पूछे गए हैं। जैसीकि काश्मीर घाटी की ला एण्ड आर्डर की स्थिति है, वह पूरे देश को मालूम है। दूर-संचार विभाग की एक अहमियत है, यह भी सब को मालूम है। पिछले अरसे वहां काफी कर्मचारी इस विभाग के मारे भी गए हैं। काफी लोगों की इसके बारे में चिंता है और पूरे सदन ने इस बारे में विचार व्यक्त किए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह संभव नहीं है कि भारतीय सेना जोकि वहां अपनी दूर-संचार व्यवस्था को देखती हैं तो क्या अपनी इस संचार विभाग की मैनिंग भारतीय सेना से कराई जा सकती है ? दूसरे, वहां पर और ज्यादा लाइनों का आटोमैटिक एक्सचेंज स्टेंड-बाय में रखा जाय क्योंकि अगर इस तरह से कोई हादसा होता है तो हमारा दुनिया से संपर्क न कटे।

श्री राजेश पायलट : सभापति जी, यहां तक घाटी का सवाल माननीय सदस्य ने किया है, वहां पर जहां जहां हमें सेना की मदद मिली है, सेना की मदद भी ली है और हर जगह यह कोशिश की कि संचार घाटी का देश और विदेश से न कटे। आज भी हर जगह जहां जहां एस.टी.डी. डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर चल सकती है, वहां चलाने की कोशिश की है और फौज की वहां पर खुली मदद रहती है। जहां-जहां हम चाहते हैं वह बेचारे हमारी मदद करते हैं और उनके सहयोग से और पैरा-मिलिटरि फोर्स के सहयोग से ठीक चल रहा है। लेकिन, मैं विस्तार में यहां बता नहीं पाऊंगा कि वहां पर हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि यहाँ वह फैक्टर जो इतना मदद नहीं कर सकता। फौज के संचार इस तरह अच्छे चलते हैं, उनका अपना एक एरिया सेक्ल्यूडेड होता है, सभापति जी। उनका सब कुछ अपनी सब जगह में होता है। हमारे जो रूटेज हैं ह सिविल एरियाज में हैं। वहां पर फौज भी इसलिए नहीं ले जा सकते कि वहां एक्सचेंज हमको फौज से चलवाना है और फौज से चलवाना है। अभी फौज और पैरा-मिलिटरी दोनों को मिलाकर एक टीम स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखी है, जहां-जहां जिसकी जिस तरह के सहयोग की जरूरत होती है, उसके सहयोग से कर रहे हैं। लेकिन, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, जब घाटी का देश और विदेश से संचार न हो सके। ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी।

गुजरात और उत्तर प्रदेश में उपमंडल मुख्यालयों पर एस० टी० डी० की सुविधा

***402. श्री ईश दत्त यादव :**
श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात और उत्तर प्रदेश में कितने उपमंडल मुख्यालयों पर एस०टी०डी० की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ; और

(ख) इन राज्यों में शेष उपमंडल मुख्यालयों पर एस०टी०डी० की सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) गुजरात के 11 उप मंडलीय मुख्यालयों तथा उत्तर प्रदेश के 79 तहसील मुख्यालयों, जो उपमंडल मुख्यालयों का कार्य भी करते हैं, को 1-4-89 से 30-11-92 की अवधि के बीच एस०टी०डी० सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

(ख) सभी उपमंडल मुख्यालयों को मार्च, 1993 तक एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

---

*सभा में यह प्रश्न श्री ईश दत्त यादव द्वारा पूछा गया।